भारत संघ और अन्य

बनाम

मैसर्स इंडसइंड बैंक लिमिटेड एवं एक अन्य

(सिविल अपील संख्या 9087-9089/2016)

15 सितंबर, 2016

[सी. नागप्पन और आर. एफ. नरीमन, न्यायाधिपतिगण]

अनुबंध अधिनियम, 1872:

धारा 28 (असंशोधित और 08.01.1997 से संशोधित) - प्रयोज्यता - अतिरिक्त-लंबे स्टेपल कपास के निर्यात के लिए कपड़ा आयुक्त द्वारा आमंत्रित आवेदन - जनवरी, 1996 में अपीलकर्ता द्वारा निर्यातकों के साथ अनुबंध निष्पादित किया गया- निर्यातकों ने 31.01.1996 को बैंक गारंटी प्रस्तुत - निर्यातक निर्धारित अवधि के भीतर निर्यात के संबंध में कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहे - नतीजतन, कपड़ा आयुक्त ने बैंक गारंटी लागू कर दी - प्रतिवादी- बैंक ने यह कहते हुए गारंटी का भुगतान करने से इनकार कर दिया कि गारंटी केवल तीन महीने की विस्तारित अवधि के भीतर यानी 30.04.1997 तक अनुबंध के अनुसार लागू की जा सकती है, बाद में नहीं - अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि बैंक धारा 28 में 08.01.1997 से संशोधन के आलोक में धारा 28 के तहत बैंक गारंटी के तहत भुगतान करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं हुआ है – अभिनिर्धारित किया : बैंक गारंटी स्वयं दिनांक 31.1.96 लाएँ, एक वर्ष बाद यानी 8.1.97 को संशोधन माफ़ी से प्रभावित नहीं होगी - धारा 28 का विषय "समझौते" है, असंशोधित धारा 28; 31.1.1996 को लागू कानून होगा, जो कि बैंक गारंटी के समझौते की तारीख है - संशोधित धारा 28 मूल कानून होने के नाते, भावी रूप से संचालित होता है, क्योंकि पूर्वव्यापीता इसकी भाषा से

स्पष्ट रूप से नहीं बताई जाती है - प्रकृति में उपचारात्मक होने के कारण, और कानून का स्पष्टीकरण या घोषणात्मक नहीं होने के कारण, संशोधित धारा 28 लागू नहीं होगी ।

क़ानून - उपचारात्मक क़ानून - संभावित अनुप्रयोग - चर्चा की गई।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया –

1. अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 में 1997 के संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के साथ विधि आयोग की रिपोर्ट को पढ़ने पर, यह उभर कर आता है कि संशोधन या तो घोषणात्मक या स्पष्टीकरणपूर्ण नहीं है। यह पहली बार यह कहते हुए कानून में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास करता है कि यहां तक कि जहां एक समझौता किसी समझौते के लिए किसी भी पक्ष के अधिकारों को समाप्त कर देता है या दायित्व का निर्वहन करता है, ताकि ऐसी पार्टी को अपने अधिकारों को लागू करने से प्रतिबंधित किया जा सके। एक निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर, ऐसा समझौता उस सीमा तक शून्य हो जाएगा। इसलिए संशोधन उन समझौतों के बीच मामले के कानून में आज तक किए गए अंतर को अलग करने का प्रयास करता है जो उस समय को सीमित करते हैं जिसके भीतर उपचार का लाभ उठाया जा सकता है और ऐसे समझौते जो समय को सीमित करने में अधिकार को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। ये स्पष्ट रूप से कानून में महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं जो उपचारात्मक प्रकृति के हैं और इनका पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता। [पैरा 19] [711-जी-एच; एच, 712-ए-बी]

1.2. मौजूदा मामले में, यह देखते हुए कि अनुबंध अधिनियम की धारा 28 का विषय "समझौते" है, असंशोधित धारा 28 31.1.1996 को लागू कानून होगा, जो बैंक गारंटी के समझौते की तारीख है। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की रूपरेखा पर यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 28 मूल कानून होने के कारण, भावी रूप से संचालित होता है क्योंकि इसकी भाषा से पूर्वव्यापीता स्पष्ट रूप से सामने नहीं आती है। प्रकृति में सुधारात्मक होने के कारण, और कानून के स्पष्टीकरण या घोषणात्मक नहीं होने के

कारण, धारा 28(बी) के अंतर्गत आने वाले कुछ समझौतों को पहली बार शून्य बनाकर, यह स्पष्ट है कि अधिकार और देनदारियां जो पक्षकारो के बीच में पहले से ही किए गए समझौतों के परिणामस्वरूप अर्जित हो चुकी हैं दूर करने की कोशिश की जाती है। ऐसा होने पर, संशोधित धारा 28 लागू नहीं होगी। [पैरा 21,25] [713-ए; 717-एफ-जी]

खाद्य निगम भारत बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (1994) 3 एससीसी 324; नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुजीर गणेश नायक एंड कंपनी (1997) 4 एससीसी 366: 1997 (3) एससीआर 202; एच.पी. राज्य वन कंपनी लिमिटेड बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2009) 2 एससीसी 252 2008 (17) एससीआर 1013 – भरोसा व्यक्त किया।

सुखराम बनाम हरभेजी [1969] 3 एस.सी.आर. 752; आर. राजगोपाल रेड्डी बनाम पद्मिनी चन्द्रशेखरन (1995) 2 एससीसी 630: 1995 (1) एससीआर 715; मिथिलेश कुमारी बनाम प्रेम बेहरल खरे (1989) 2 एससीसी 95: 1989 (1) एससीआर 621; पूर्वांचल केबल्स एंड कंडक्टर्स (पी) लिमिटेड बनाम असम एसईबी (2012) 7 एससीसी 462: 2012 (6) एससीआर 905; सीआईटी बनाम वाटिका टाउनशिप (पी) लिमिटेड (2015) 1 एससीसी 1: 2014 (12) एससीआर 1037 संदर्भित किया गया।

भारतीय विधि आयोग की 13 वीं रिपोर्ट, 1958; भारतीय विधि आयोग की 97 वीं रिपोर्ट, 1984 – संदर्भित की गई।

प्रकरण कानून संदर्भ

[1969] 3 एस.सी.आर. 752	संदर्भित किया गया	पैरा 20
1995 (1) एससीआर 715	संदर्भित किया गया	पैरा 22
1989 (1) एससीआर 621	संदर्भित किया गया	पैरा 22
2012 (6) एससीआर 905	संदर्भित किया गया	पैरा 23

2014 (12) एससीआर 1037 संदर्भित किया गया पैरा 24

(1994) 3 एससीसी 324 भरोसा व्यक्त किया पैरा 29

1997 (3) एससीआर 202 भरोसा व्यक्त किया पैरा 33

2008 (17) एससीआर 1013 भरोसा व्यक्त किया पैरा 35

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 9087-9089/2016

अपील संख्या 258/2008, 259/2008 और 260/2008 में बॉम्बे के उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 20.04.2011 से।

ए.के. पांडा, वरिष्ठ अधिवक्ता, आर.के. राठौड़, विभु शंकर मिश्रा, ए. सुश्री मनिता वर्मा, सुश्री अरुणिमा द्विवेदी, सुश्री श्रुति श्रीवास्तव, राज बहादुर यादव, एम.के. मरोरिआ (श्रीकांत एन. टेरडल के लिये), अधिवक्तागण अपीलकर्ताओं के लिए.

डॉ. ए. एम. सिंघवी, कृष्णन वेणुगोपाल, वरिष्ठ वकील, प्रणब कुमार मलिक, सुश्री सोमा मलिक, सेबत कुमार देवरिया, अमित भंडार, ललित भसीन, सुश्री नीना गुप्ता, मुदित शर्मा, पी. वी. योगेश्वरन, सुश्री रानू पुरोहित, सुश्री शेस अधिवक्तागण, प्रतिवादीगण के लिए।

न्यायालय का निर्णय आर.एफ. नरीमन, न्यायाधिपति, द्वारा दिया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. भारत संघ की वर्तमान अपीलें अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 में 1997 के संशोधन की प्रयोज्यता के बारे में एक दिलचस्प सवाल उठाती हैं। तीन अपीलों के तथ्य समान हैं क्योंकि वे चार निर्यातकों से संबंधित हैं जो जीपीबी समूह की कंपनियो से संबंधित है।

3. आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के तहत कपड़ा आयुक्त द्वारा जारी दिनांक 6.11.1995 के एक ज्ञापन द्वारा, सितंबर, 1995-अगस्त, 1996 के लिए कच्चे

कपास और कपास अपशिष्ट के निर्यात के लिए नियम और शर्तें निर्धारित की गईं। शिपमेंट की अनुमति केवल अपरिवर्तनीय साख पत्र के आधार पर दी गई थी। निर्यातकों को अनुबंध मूल्य के 10% की दर पर निर्धारित प्रपत्र में बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। शिपमेंट की अंतिम तिथि के बाद अतिरिक्त तीन महीने के दावों के प्रावधान के साथ बैंक गारंटी को 6 महीने तक वैध रखना आवश्यक था। कोटा का आवंटन उच्चतम इकाई मूल्य प्राप्ति के आधार पर किया गया था।

4. कपड़ा आयुक्त ने अतिरिक्त लंबे स्टेपल कपास की 10,000 गांठों के निर्यात के लिए दिनांक 9.1.1996 के प्रेस नोट और ज्ञापन दोनों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए। प्रेस नोट और ज्ञापन में उल्लेख किया गया था कि शिपमेंट अवधि कोटा के पंजीकरण की तारीख से 180 दिन या 31.8.1996 तक, जो भी पहले हो, होगी।

5. इस प्रेस नोट और ज्ञापन के अनुसार, मेसर्स इंडोकोमेक्स फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर और चार निर्यातको के बीच, सभी को जनवरी, 1996 में, चार बिक्री अनुबंध निष्पादित किए गए। 31.1.1996 को, चारों निर्यातकों ने सम तारीख की बैंक गारंटी के साथ एक साथ आवेदन किया। फरवरी में, निर्यातकों को 31.7.1996 तक शिपमेंट की वैधता अवधि के भीतर दिनांक 6.2.1996 के आवंटन-सह-पंजीकरण प्रमाणपत्र के माध्यम से 9175 गांठों की कुल मात्रा का निर्यात करने की अनुमति दी गई थी। यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस तिथि को तीन बार बढ़ाया गया था, तीसरा विस्तार 28.2.1997 तक अधिसूचित किया गया था।

6. चूंकि चार निर्यातक निर्धारित अवधि के भीतर उन्हें आवंटित माल के निर्यात के संबंध में सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहे और उपेक्षा की, कपड़ा आयुक्त ने दिनांक 3.1.1997 के एक पत्र द्वारा निर्यातकों से 15 दिनों के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा करने को कहा। इस पत्र के जारी होने की तारीख लेकिन 20.1.1997 के बाद नहीं, ऐसा न होने पर बैंक गारंटी लागू कर दी जाएगी। चूंकि निर्यातक इन दस्तावेजों को

प्रस्तुत करने में विफल रहे और उपेक्षा की, कपड़ा आयुक्त ने दिनांक 15.5.1997 के पत्र के माध्यम से बैंक गारंटी वापस ले ली। सम तारीख के पत्रों के माध्यम से, प्रतिवादी बैंक ने उक्त गारंटी के तहत भुगतान करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि इसे केवल तीन महीने की विस्तारित अवधि के भीतर यानी 30.4.1997 तक लागू किया जा सकता है, और उसके बाद नहीं। दिनांक 27/28.8.1997 को एक पत्र द्वारा, कपड़ा आयुक्त ने प्रतिवादी बैंक को सूचित किया कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 28 में संशोधन के आलोक में, जो 8.1.1997 को लागू हुआ, बैंक अपने दायित्व से मुक्त नहीं है। बैंक गारंटी के तहत भुगतान करें। इस पर, बैंक ने दिनांक 19.9.1997 के पत्र के माध्यम से अपने पहले के रुख को दोहराया और कहा कि वह 30.4.1997 के बाद बैंक गारंटी के तहत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि उपरोक्त समूह की दो कंपनियों, अर्थात् जीपीबी फाइबर्स लिमिटेड और मेसर्स भगवती कॉटन लिमिटेड का विलय 12.9.1997 को किया गया था।

7. 23.7.1998 को, कपड़ा आयुक्त ने निर्यातकों और प्रतिवादी बैंक दोनों को बैंक गारंटी द्वारा कवर की गई राशि का भुगतान करने के लिए बुलाया। चूंकि इस पत्र का कोई जवाब नहीं आया, इसलिए भारतीय संघ और कपड़ा आयुक्त द्वारा निर्यातकों और बैंक के खिलाफ 8.4.1999 को तीन संक्षिप्त मुकदमे - 2959/1999, 2963/1999 और 2996/1999- बम्बई उच्च न्यायालय में दायर किए गए। आदेश दिनांक 4.12.2001 द्वारा, जैसा कि 22.1.2002 को संशोधित किया गया था, बैंक को मुकदमों की रक्षा के लिए बिना शर्त अनुमति दी गई थी, और उक्त आदेश की दिनांक से 12 सप्ताह के भीतर न्यायालय में 3,82,59,450/- रुपये की राशि जमा करने पर निर्यातकों को मुकदमों की रक्षा करने की सशर्त छुट्टी दी गई थी। 20.1.2003 / 27.2.2003 को, खंडपीठ ने भारत संघ द्वारा दायर अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के

खंड 15 के तहत सुनवाई योग्य नहीं थी। 14.8.2003 को, भारत संघ द्वारा दायर एक एसएलपी का भी यही हश्र हुआ।

8. सभी चार निर्यातक एक पक्षीय रहे, जिसके परिणामस्वरूप 29.11.2004 को उक्त निर्यातकों के विरुद्ध वादों का एक पक्षीय फैसला सुनाया गया।

9. बैंक के साथ विवाद पर, 22.2.2008 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश का विचार था कि चूंकि प्रश्न में बैंक गारंटी 8.1.1997 को लागू थी, जब अनुबंध अधिनियम की धारा 28 में संशोधन किया गया था , संशोधित धारा 28 इन मामलों के तथ्यों पर लागू होगी। ऐसा होने पर, यदि बैंक गारंटी की समाप्ति की तारीख के तीन महीने के भीतर दावा नहीं किया जाना था, तो बैंक के अधिकारों को समाप्त करने और बैंक के दायित्व का निर्वहन करने की गारंटी देने वाला खंड शून्य माना गया था। नतीजतन, यह माना गया कि उपरोक्त समय की बाधा के बिना, उपरोक्त बैंक गारंटी का आह्वान वैध था, और इसलिए, उक्त मुकदमों का फैसला भारत संघ के पक्ष में और बैंक के खिलाफ किया गया।

10. इस फैसले के खिलाफ एक अपील में, दिनांक 20.4.2011 के आक्षेपित फैसले द्वारा, बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने यह मानते हुए कि संशोधित धारा 28 इन मामलों के तथ्यों पर लागू होगी, निम्नलिखित द्वारा विपरीत निष्कर्ष पर पहुंची इस न्यायालय के कुछ निर्णयों ने, और इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश को उलट दिया, यह मानते हुए कि चूंकि बैंक गारंटी निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं की गई थी, इसलिए मुकदमों को खारिज करना होगा। भारत संघ ने हमारे समक्ष वर्तमान अपीलें दायर की हैं।

11. श्री ए.के.पांडा भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा है कि एकल न्यायाधीश ने 1997 में संशोधित धारा 28 (बी) को लागू करने में सही था, और बैंक गारंटी में निहित यह शर्त जो उस अवधि को प्रतिबंधित करता है जिसके भीतर

इसे लागू किया जा सकता है, शून्य है। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने (1995) 2 एससीसी 630, आर. राजगोपाल रेड्डी बनाम पद्मिनी चन्द्रशेखरन का हवाला दिया। विद्वान वकील के अनुसार, खंडपीठ ने दोहराया कि संशोधित धारा 28(बी) लागू होगी, लेकिन उसका यह निष्कर्ष सही नहीं था कि बैंक गारंटी में ऐसा खंड शून्य नहीं होगा। विद्वान वकील के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया, वे सभी पूर्व-संशोधन थे, और इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश के विपरीत परिणाम पर पहुंचने के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था।

12. दूसरी ओर, डॉ. ए.एम. सिंघवी विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णन वेणुगोपाल ने तर्क दिया कि धारा 28 में संशोधन को लागू करने में एकल न्यायाधीश और खंडपीठ दोनों सही नहीं थे। दोनों विद्वान वकील के अनुसार, बैंक स्वयं दिनांक 31.1.1996 होने की गारंटी देता है, एक वर्ष बाद अर्थात् 8.1.1997 को किये गये संशोधन से प्रभावित नहीं होगा। प्रासंगिक तिथि और लागू होने वाला प्रासंगिक कानून 31.1.1996 को होगा, जो कि असंशोधित धारा 28 होगा। यह मामला है, उनके अनुसार, निण्रयो के एक समूह ने माना है कि यदि अनुबंध में कोई खंड प्रतिबंधित नहीं करता है वह सीमा अवधि जिसके भीतर कोई न्यायालय से संपर्क कर सकता है, तो यह पूरी तरह से वैध है और धारा 28 (असंशोधित) से प्रभावित नहीं है। इस उद्देश्य से उन्होंने हमारे सामने कई निर्णयों का हवाला दिया। उनके द्वारा एक वैकल्पिक दलील भी उठाई गई थी कि, इस धारणा पर कि संशोधित धारा 28 लागू होगी, फिर भी, संशोधन द्वारा प्राप्त की जाने वाली सीमित वस्तु को ध्यान में रखते हुए, जो विधि आयोग की रिपोर्ट के बाद यह स्पष्ट होगी कि धारा 28(बी) के लागू होने पर भी, बैंक गारंटी में उपरोक्त खंड प्रभावित नहीं होगा। विशेष रूप से, उन्होंने तर्क दिया कि विधि आयोग द्वारा सुझाई गई संशोधित धारा 28 वास्तव में धारा 28(बी) में शब्दशः लागू नहीं की गई थी, और संशोधित धारा 28 में महत्वपूर्ण शब्द "या दावा करने में विफलता पर" गायब हैं। उन्होंने अपने

तर्कों के दौरान, विशेष रूप से बैंक गारंटी से संबंधित, 2012 में धारा 28 के बाद के संशोधन का भी उल्लेख किया।

13. प्राथमिक विवाद जिसका हम सामना कर रहे हैं वह यह है कि क्या धारा 28 अपने मूल रूप में लागू होती है या क्या यह 1997 में संशोधन के बाद में लागू होती है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे पहले धारा 28 को उसके मूल रूप में और धारा 28 को संशोधन के बाद निर्धारित करना आवश्यक है। धारा इस प्रकार पठनीय है:-

मूल अनुभाग

28. प्रत्येक समझौता, जिसके द्वारा किसी भी पक्ष को सामान्य न्यायाधिकरणों में सामान्य कानूनी कार्यवाही द्वारा किसी भी अनुबंध के तहत या उसके संबंध में अपने अधिकारों को लागू करने से पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाता है, या जो उस समय को सीमित करता है जिसके भीतर वह इस प्रकार अपने अधिकारों को लागू कर सकता है, उस सीमा तक शून्य है।

संशोधन दिनांक से 08.01.1997 प्रभावी

28. कानूनी कार्यवाही में बाधा डालने वाले समझौते शून्य होंगे, हर समझौता,

(ए) जिसके द्वारा किसी भी पक्ष को सामान्य न्यायाधिकरणों में सामान्य कानूनी कार्यवाही द्वारा किसी अनुबंध के तहत या उसके संबंध में अपने अधिकारों को लागू करने से पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाता है, या जो उस समय को सीमित करता है जिसके भीतर वह अपने अधिकारों को लागू कर सकता है, उस सीमा तक शून्य है;

(बी) जो एक निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर किसी भी अनुबंध के तहत या उसके संबंध में किसी भी पक्ष के अधिकारों को समाप्त कर देता है, या उसके किसी भी पक्ष को किसी भी दायित्व से मुक्त कर देता है, ताकि किसी भी पक्ष को सामान्य कानूनी कार्यवाही द्वारा अपने अधिकारों को लागू करने से प्रतिबंधित किया जा सके, उस सीमा तक शून्य है।"

14. इस प्राथमिक प्रश्न का उत्तर देने के लिए, हमें पहले यह देखना होगा कि क्या धारा 28 में किए गए बदलाव को कानून का स्पष्टीकरण या घोषणात्मक कहा जा सकता है, और इसलिए पूर्वव्यापी कहा जा सकता है। यह सामान्य आधार है कि क़ानून ने उपरोक्त संशोधन को पूर्वव्यापी नहीं बनाया है क्योंकि यह केवल 8.1.1997 से लागू होना है।

15. मूल खंड 1872 विंटेज का है। यह 100 से अधिक वर्षों तक इसी अवतार में रहा और दो विधि आयोग रिपोर्टों का विषय रहा। भारत के विधि आयोग की 13 वीं रिपोर्ट, सितंबर, 1958 ने इस धारा की जांच की और अंततः निर्णय लिया कि इस तथ्य को देखते हुए कि इसमें संशोधन करना आवश्यक नहीं था, इस तथ्य को देखते हुए कि अधिकार के त्याग के साथ-साथ उपचार के विरुद्ध समझौते के बीच एक सुविख्यात अंतर है, जबकि केवल उपचार के त्याग के लिए समझौते के बीच एक प्रसिद्ध अंतर है। यह रिपोर्ट के पैरा 57 में इस प्रकार दर्शाया गया है:-

"57. निर्णित मामले इस धारा की प्रयोज्यता के संदर्भ में बीमा पॉलिसियों के कुछ खंडों के संबंध में राय की भिन्नता को प्रकट करते हैं। जांच करने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि ये मामले वास्तव में धारा की व्याख्या पर नहीं, बल्कि प्रश्न में बीमा पॉलिसियों का निर्माण पर निर्भर करते हैं। यह सिद्धांत स्वयं अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि अधिकारों और उपचारों के त्याग के लिए एक समझौता वैध है, लेकिन उपचारों के त्याग

के लिए एक समझौता केवल धारा 28 के दायरे में आता है। इस प्रकार, हमारी राय में न्यायिक प्राधिकार के उपरोक्त टकराव के कारण किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।"

16. कई दशक बीत गए, जब तक कि विधि आयोग ने मार्च, 1984 की अपनी 97 वीं रिपोर्ट में स्वत: निर्णय नहीं लिया कि धारा में संशोधन की आवश्यकता है। रिपोर्ट के परिचय में विचारणीय बिंदु इस प्रकार बताया गया है:-

"1.2 भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 के तहत- बिंदु को संक्षेप में बताने के लिए - एक समझौता जो उस समय को सीमित करता है जिसके भीतर एक समझौते का पक्ष अदालत में कार्यवाही द्वारा किसी भी अनुबंध के तहत अपने अधिकारों को लागू कर सकता है, उस सीमा तक अमान्य है । लेकिन धारा नुस्खे की प्रकृति में किसी समझौते को अमान्य नहीं करती है, यानी एक समझौता जो एक निर्दिष्ट अवधि के अंत में प्रदान करता है। यदि इसके तहत अधिकारों को लागू नहीं किया जाता है, तो अधिकारों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा जैसा कि इस रिपोर्ट के बाद के अध्यायों में अधिक विस्तार से बताया जाएगा, यह स्थिति अनावश्यक मुकदमेबाजी को जन्म देने के अलावा, गंभीर विसंगतियां और कठिनाई पैदा करती है। प्रथम दृष्टया, आयोग को यह प्रतीत हुआ कि धारा को इस बिंदु पर सुधार की आवश्यकता है। धारा में संशोधन के पक्ष और विपक्ष में तर्क बाद में दिए जाएंगे। फिलहाल, यह बताना पर्याप्त है कि यह समस्या काफी व्यावहारिक महत्व की है क्योंकि ऐसी शर्तें अक्सर व्यापार के दौरान किए गए समझौतों में पाई जाती हैं।"

17. मौजूदा केस कानून का अध्ययन करने और यह पता लगाने के बाद कि मौजूदा केस कानून में असमान सौदेबाजी की शक्ति के कारण आर्थिक अन्याय हुआ, विधि

आयोग ने धारा में बदलाव की सिफारिश करने का फैसला किया। यह इस प्रकार किया गया:-

"5.1 अब हम उन परिवर्तनों पर आते हैं जिनकी वर्तमान कानून में आवश्यकता है। हमारी राय में, अनुबंधों में निर्देशात्मक खंडों की वर्तमान कानूनी स्थिति का न्याय, तर्क, सामान्य ज्ञान या सुविधा के मामले के रूप में बचाव नहीं किया जा सकता है। ऐसे खंडों को स्वीकार करते समय, उपभोक्ताओं को या तो ऐसे खंडों के संभावित प्रतिकूल प्रभाव का एहसास नहीं होता है, या उन्हें सहमत होने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि बड़े निगम इन कठिन शर्तों को छोड़कर अनुबंध में प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। "यह ले लो या सबकुछ छोड़ दो", उनका सामान्य रवैया है, और क्योंकि उनकी बेहतर सौदेबाजी की शक्ति के कारण, स्वाभाविक रूप से उनका पलड़ा भारी है। हम, वर्तमान में, "मानक प्रपत्र अनुबंध" या "मानक" शर्तों के बहुत व्यापक क्षेत्र से निपट नहीं रहे हैं। लेकिन खुद को चर्चा के तहत संकीर्ण मुद्दे तक ही सीमित रखते हुए, यह ऐसा प्रतीत होगा कि वर्तमान कानूनी स्थिति आम आदमी के दृष्टिकोण से गंभीर आपत्ति के लिए खुली है।

इसके अलावा, ऐसे खंड लेनदेन में अनिश्चितता का तत्व पेश करते हैं जो प्रतिदिन सैकड़ों व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं।

5.2 वर्तमान कानून के अवगुणों के बारे में हमने पिछले अध्यायों में जो कुछ कहा है, उसे दोहराना शायद ही आवश्यक है। संक्षेप में, कोई यह कह सकता है कि वर्तमान कानून, जो निर्देशात्मक खंडों को वैध मानता है, जबकि समय सीमा खंडों को अमान्य करता है, जो केवल उपचार पर रोक लगाते हैं, निम्नलिखित प्रमुख दोषों से ग्रस्त हैं:

(ए) यह उन लोगों के लिए गंभीर कठिनाई का कारण बनता है जो आर्थिक रूप से वंचित हैं और आर्थिक न्याय का उल्लंघन है।

(बी) विशेष रूप से, बडे निकायो से निपटते हुये यह उपभोक्ता के हितों को नुकसान पहुँचाता है।

(सी) यह अतार्किक है, एक भेद पर आधारित है जो अधिक गंभीर दोष को वैध मानता है, जबकि कम को अमान्य करता है।

(डी) यह व्यवहार में आसान अनुप्रयोग को स्वीकार करने के लिए बहुत सूक्ष्म और परिष्कृत भेद पर आधारित है। इस प्रकार, यह पार्टियों के अधिकारों पर एक बादल डालता है, जो निश्चित रूप से नहीं जानते कि वे कहाँ खड़े हैं, अंततः परिहार्य मुकदमेबाजी की ओर ले जाता है।

5.3 मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने पर, हम अनुशंसा करते हैं कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए ताकि अमान्य संविदात्मक खंडों को प्रस्तुत करने के लिए संशोधन किया जा सके, जो अनुबंध से अर्जित एक निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाते हैं। यहां धारा 28 के मुख्य पैराग्राफ को फिर से तैयार करने का सुझाव दिया गया है।

संशोधित धारा 28, मुख्य पैराग्राफ, अनुबंध अधिनियम जैसा अनुशंसित किया गया

28. प्रत्येक समझौता -

(ए) जिसके द्वारा किसी भी पक्ष को सामान्य न्यायाधिकरणों में सामान्य कानूनी कार्यवाही द्वारा किसी अनुबंध के तहत या उसके संबंध में अपने अधिकारों को लागू करने से पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाता है, या

(बी) जो उस समय को सीमित करता है जिसके भीतर वह अपने अधिकारों को लागू कर सकता है, या

(सी) जो एक निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर (या दावा करने में विफलता पर) या एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू करने पर किसी भी अनुबंध के तहत या उसके संबंध में किसी भी पक्ष के अधिकारों को समाप्त कर देता है, या

(डी) जो खंड (सी) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में किसी भी अनुबंध के तहत या उसके संबंध में किसी भी दायित्व से किसी भी पक्ष को मुक्त करता है, उस सीमा तक शून्य है।

18. इस रिपोर्ट को लागू किये जाने के बाद 13 वर्ष की अवधि बीत गयी। संशोधन के उद्देश्यों और कारणों का विवरण निम्न प्रकार पठनीय है-

"भारत के विधि आयोग ने अपनी 97 वीं रिपोर्ट में सिफारिश की है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 में संशोधन किया जा सकता है ताकि मौजूदा धारा द्वारा बनाई गई विषम स्थिति को ठीक किया जा सके। अदालतों द्वारा यह माना गया है कि उक्त धारा 28 किसी भी समझौते में केवल उस खंड को अमान्य कर देगा जो किसी भी पक्ष को उसके अधिकारों को पूरी तरह से लागू करने से रोकता है या जो उस समय को सीमित करता है जिसके भीतर वह अपने अधिकारों को लागू कर सकता है। हालांकि, अदालतों ने माना है कि यह धारा तब लागू नहीं होगी जब अनुबंध लागू हो यह शब्द किसी पक्ष के मुकदमा करने के अधिकार को समाप्त कर देता है या किसी पक्ष को दावे के संबंध में सभी दायित्वों से मुक्त कर देता है। इस प्रकार धारा 28 से जो प्रभावित होता है वह केवल उपचार को त्यागने वाला एक समझौता है यानी जहां समय-

सीमा होती है समझौते में निर्दिष्ट कानून द्वारा प्रदान की गई सीमा की अवधि से कम है। उपाय और अधिकार के बीच एक अंतर मौजूद माना जाता है और यह अंतर वर्तमान स्थिति का आधार है जिसके तहत एक उपाय को रोकने वाला खंड शून्य है, लेकिन एक खंड जो अधिकार को को समाप्त करता है, वैध है। यह दृष्टिकोण सैद्धांतिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन व्यवहार में, यह गंभीर कठिनाई का कारण बनता है और इसका दुरुपयोग भी हो सकता है।

2. ऐसा महसूस किया गया कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 में संशोधन किया जाना चाहिए क्योंकि यह बड़े निगमों से जुड़े उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचाता है और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के लिए गंभीर कठिनाई का कारण बनता है।

3. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

19. संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के साथ विधि आयोग की रिपोर्ट को पढ़ने पर जो बात सामने आती है वह यह है कि संशोधन का तात्पर्य घोषणात्मक या स्पष्टीकरणात्मक होना नहीं है। यह पहली बार यह कहते हुए कानून में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास करता है कि यहां तक कि जहां एक समझौता किसी समझौते के लिए किसी भी पक्ष के अधिकारों को समाप्त कर देता है या दायित्व का निर्वहन करता है, ताकि ऐसे पक्षकार को किसी निर्दिष्ट समयावधि की समाप्ति पर अपने अधिकारों को लागू करने से प्रतिबंधित किया जा सके। ऐसा समझौता उस सीमा तक शून्य हो जाएगा। इसलिए संशोधन उन समझौतों के बीच आज तक के मामले के कानून में किए गए अंतर को अलग करने का प्रयास करता है जो समय सीमा को सीमित करते हैं। कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं और ऐसे समझौते जो इतने सीमित समय में अधिकार को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। ये स्पष्ट रूप से कानून में

महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं जो उपचारात्मक प्रकृति के हैं और इनका पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता।

20. सुखराम बनाम हरभेजी, [1969] 3 एस.सी.आर. 752 में, इस न्यायालय ने कहा:-

"अब कोई कानून निस्संदेह पूर्वव्यापी है यदि कानून स्पष्ट रूप से ऐसा कहता है लेकिन कानून को पूर्वव्यापी बनाने के लिए हमेशा स्पष्ट रूप से ऐसा कहना आवश्यक नहीं है। ऐसे अवसर होते हैं जब किसी कानून को संचालन में पूर्वव्यापी माना जा सकता है। पूर्वव्यापी धारणा को अन्य तरीके से नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन कई क़ानूनों को बिना किसी घोषणा के पूर्वव्यापी माना गया है। इस प्रकार यह है कि उपचारात्मक क़ानूनों को हमेशा संभावित माना जाता है लेकिन घोषणात्मक क़ानूनों को पूर्वव्यापी माना जाता है। इसी तरह कभी-कभी क़ानूनों का पूर्वव्यापी प्रभाव होता है जब घोषित इरादा स्पष्ट रूप से होता है और विशेष कानून में या संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में प्रयुक्त भाषा से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। यह हमेशा एक सवाल है कि क्या विधायिका ने खुद को पर्याप्त रूप से व्यक्त किया है। इसे खोजने के लिए अधिनियम और उपाय के सामान्य दायरे और दायरे को देखना होगा विधायिका कानून की पूर्व स्थिति को लागू करने का इरादा रखती है और फिर यह निर्धारित करती है कि विधायिका क्या करना चाहती है। निःसंदेह, जांच का यह दायरा केवल तभी खुला है जब यह आवश्यक हो। मेन बनाम स्टार्क [1890] 15 ए.सी. 384 एट 388 में लॉर्ड सेलबोर्न के शब्दों में, किसी अधिनियम के संदर्भ में या उसकी भाषा से एकत्रित कुछ ऐसा हो सकता है, जो शब्दों को प्रथम दृष्टया एक बड़े ऑपरेशन की संभावना दे सकता है। विधायिका के अभिव्यक्त या स्पष्ट रूप से निहित इरादे से जो इकट्ठा

किया जा सकता है, उससे अधिक पूर्वव्यापीता नहीं दी जानी चाहिए।" (पृ. 758-759)

21. यह ध्यान में रखते हुए कि धारा 28 का विषय "समझौता" है, असंशोधित धारा 28; 31.1.1996 को लागू कानून होगा, जो बैंक गारंटी के समझौते की तारीख है। अब यह हमारा काम है कि हम दोनों पक्षों द्वारा उद्धृत मामले के कानून से निपटें।

22. आर. राजगोपाल रेड्डी बनाम पद्मिनी चंद्रशेखरन, (1995) 2 एससीसी 630 में, इस न्यायालय को बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 की व्याख्या करने के लिए बुलाया गया था। इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने मिथिलेश कुमारी बनाम प्रेम को खारिज कर दिया। बिहारी खरे, (1989) 2 एससीसी 95, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 1988 का अधिनियम संभावित था न कि पूर्वव्यापी। खंडपीठ के फैसले को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि अधिनियम स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी नहीं है, इसलिए जांच की जाएगी कि क्या इसे स्पष्टीकरण या घोषणात्मक कहा जा सकता है। क़ानून की धारा 4(1) की भाषा ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह 1988 अधिनियम लागू होने के बाद दायर किए गए मुकदमों पर ही लागू होगा। इसके अलावा, बेंच ने व्याख्या पर मैक्सवेल को इस प्रकार उद्धृत किया:

> "संभवतः निर्माण का कोई भी नियम इससे अधिक मजबूती से स्थापित नहीं हुआ है - कि किसी क़ानून को पूर्वव्यापी संचालन नहीं दिया जाना चाहिए ताकि किसी मौजूदा अधिकार या दायित्व को ख़राब किया जा सके, अन्यथा प्रक्रिया के मामलों के संबंध में, जब तक कि अधिनियम की भाषा के साथ हिंसा करते हुये उस प्रभाव को टाला नहीं जा सकता। यदि अधिनियम उस भाषा में व्यक्त किया गया है जो व्याख्या करने में काफी सक्षम है, तो इसे केवल संभावित माना जाना चाहिए।' वास्तव में, नियम के दो पहलू हैं, इसके लिए, 'इसमें एक और अधीनस्थ नियम

शामिल है, जिसका अर्थ यह है कि एक क़ानून का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि इसकी भाषा की तुलना में अधिक पूर्वव्यापी संचालन आवश्यक है।" [पैरा 14]

इसके बाद यह इस प्रकार कायम रहा:

"जहां तक कारण 3 का संबंध है, हमारा विचार है कि अधिनियम को प्रकृति में घोषणात्मक नहीं माना जा सकता है। घोषणात्मक अधिनियम पहले से मौजूद लेनदेन या अधिनियमन के संबंध में विधायिका के वास्तविक इरादे की घोषणा और स्पष्ट करता है, यह नहीं अधिकार और दायित्व नहीं बनाता है। धारा 3 की स्पष्ट भाषा में, अधिनियम को घोषणात्मक नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में यह प्रकृति में निषेधात्मक है और बेनामी संपत्तियों के वास्तविक मालिक के अधिकारों को नष्ट करने का प्रयास करता है और इस संबंध में इसने अधिकार छीन लिया है। मुकदमा दायर करने के लिए या बेनामीदार द्वारा किसी मुकदमे में ऐसा बचाव करने के लिए दोनों ही वास्तविक मालिक हैं। ऐसा अधिनियम जो बेनामी लेनदेन पर रोक लगाता है और ऐसे लेनदेन से मिलने वाले अधिकारों को नष्ट कर देता है जो पहले मौजूद थे, वास्तव में एक घोषणात्मक अधिनियम नहीं है। सम्मान के साथ, हम उस तर्क की पंक्ति से असहमत हैं जो खंडपीठ को आदेश दिया गया था। इस संबंध में, हम वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों, 5 वें संस्करण, 1992 में श्री जी.पी. सिंह, पृष्ठ 315 द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं। 'घोषणात्मक क़ानून' शीर्षक के अंतर्गत:

पूर्वव्यापी संचालन के खिलाफ धारणा घोषणात्मक क़ानूनों पर लागू नहीं है। जैसा कि क्रेज़ में कहा गया है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित है:

"आधुनिक उद्देश्यों के लिए एक घोषणात्मक अधिनियम को सामान्य कानून, या किसी क़ानून के अर्थ या प्रभाव के बारे में मौजूदा संदेह को दूर करने के लिए एक अधिनियम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऐसे अधिनियमों को आमतौर पर पूर्वव्यापी माना जाता है। एक घोषणात्मक अधिनियम पारित करने का सामान्य कारण है जिसे संसद न्यायिक त्रुटि मानती है, चाहे वह आम कानून के बयान में हो या क़ानून की व्याख्या में, उसे अलग रखना। आम तौर पर, यदि हमेशा नहीं, तो ऐसे अधिनियम में एक प्रस्तावना होती है, और "घोषित" शब्द के साथ साथ अधिनियमित शब्द भी।'

लेकिन 'यह घोषित है' शब्दों का उपयोग यह निर्णायक नहीं है कि अधिनियम घोषणात्मक है क्योंकि इन शब्दों का उपयोग कभी-कभी कानून के नए नियमों को पेश करने के लिए किया जा सकता है और बाद के मामले में अधिनियम केवल कानून में संशोधन करेगा और आवश्यक रूप से पूर्वव्यापी नहीं होगा। इसलिए, अधिनियम की प्रकृति का निर्धारण करते समय, स्वरूप के बजाय सार पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि किसी नए अधिनियम को पहले के अधिनियम की व्याख्या करनी है, तो यह तब तक निरर्थक होगा जब तक कि इसे पूर्वव्यापी न समझा जाए। एक व्याख्यात्मक अधिनियम आम तौर पर एक स्पष्ट चूक प्रदान करने या पिछले अधिनियम के अर्थ के बारे में संदेह को दूर करने के लिए पारित किया जाता है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि

कोई क़ानून उपचारात्मक है या पिछले कानून की केवल घोषणात्मक है तो आम तौर पर पूर्वव्यापी कार्रवाई का इरादा है। 'हमेशा इसका मतलब समझा जाएगा' भाषा घोषणात्मक है, और स्पष्ट शब्दों में पूर्वव्यापी है। यह इंगित करने वाले स्पष्ट शब्दों के अभाव में कि संशोधित अधिनियम घोषणात्मक है, इसका अर्थ तब नहीं लगाया जाएगा जब पूर्व-संशोधित प्रावधान स्पष्ट और स्पष्ट था। एक संशोधन अधिनियम मूल अधिनियम के एक प्रावधान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए पूरी तरह से स्पष्ट हो सकता है जो पहले से ही अंतर्निहित था। इस प्रकृति के एक स्पष्टीकरण संशोधन का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा और इसलिए, यदि संविधान लागू होने पर मुख्य अधिनियम मौजूदा कानून था तो संशोधन अधिनियम भी मौजूदा कानून का हिस्सा होगा।

मिथिलेश कुमारी बनाम प्रेम बिहारी खरे [(1989) 2 एससीसी 95 (1989) 1 एससीआर 621] में, यह प्रस्तुत किया गया है कि बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 की धारा 4 को गलत तरीके से प्रकृति में एक अधिनियम घोषणात्मक माना गया था। इसे सामान्य कानून या किसी क़ानून के अर्थ या प्रभाव के संबंध में मौजूद किसी भी संदेह को दूर करने के लिए पारित नहीं किया गया था। हालाँकि, यह निष्कर्ष कि धारा 4 पिछले बेनामी लेनदेन पर भी लागू होती है, धारा में प्रयुक्त भाषा के आधार पर समर्थित हो सकती है।" [पैरा 17]

23. इसी तरह, पूर्वांचल केबल्स एंड कंडक्टर्स (पी) लिमिटेड बनाम असम एसईबी, (2012) 7 एससीसी 462 में, इस न्यायालय को यह तय करना था कि क्या छोटे पैमाने और सहायक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज अधिनियम, 1993 के

तहत पूर्वव्यापी कहा जा सकता है। इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों की समीक्षा के बाद, इस न्यायालय ने कहा:-

> "इस तथ्य के बारे में कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम एक वास्तविक कानून है क्योंकि भुगतान में देरी के मामले में ब्याज की उच्च दर का अधिकार आपूर्तिकर्ता के पक्ष में जाता है और खरीदार पर संबंधित दायित्व लगाया जाता है। यह न्यायालय ने बार-बार देखा है कि कोई भी मूल कानून तब तक भावी रूप से संचालित होगा जब तक कि क़ानून की भाषा में पूर्वव्यापी संचालन स्पष्ट रूप से नहीं किया गया हो। केवल एक प्रक्रियात्मक या घोषणात्मक कानून पूर्वव्यापी रूप से संचालित होता है क्योंकि प्रक्रिया में कोई निहित अधिकार नहीं होता है।
>
> अधिनियम के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के किसी स्पष्ट विधायी इरादे के अभाव में, और इस तथ्य के आधार पर कि अधिनियम खरीदार के खिलाफ उच्च ब्याज दर का एक नया दायित्व बनाता है, अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव वाला नहीं माना जा सकता है। चूंकि अधिनियम में परिकल्पना की गई है कि आपूर्तिकर्ता को अधिनियम के संदर्भ में उच्च ब्याज दर का दावा करने का अर्जित अधिकार है, इसे केवल अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख यानी 23-9-1992 के बाद बिक्री समझौतों के लिए अर्जित किया जा सकता है। किसी समय पहले नहीं।" [पैरा 51 और 52]

24. इसी तरह, सीआईटी बनाम वाटिका टाउनशिप (पी) लिमिटेड, (2015) 1 एससीसी 1 में, इस न्यायालय ने माना कि भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 113 का प्रावधान संभावित था और पूर्वव्यापी नहीं था। ऐसा कहते हुए, संविधान पीठ ने कुछ सामान्य सिद्धांतों को इस प्रकार अपनाया: -

"किसी कानून की व्याख्या कैसे की जानी है, इसका मार्गदर्शन करने वाले विभिन्न नियमों में से एक स्थापित नियम यह है कि जब तक कोई विपरीत इरादा प्रकट न हो, तब तक यह माना जाता है कि किसी कानून का पूर्वव्यापी संचालन का इरादा नहीं है। नियम के पीछे विचार यह है कि एक मौजूदा कानून होना चाहिए वर्तमान गतिविधियों को नियंत्रित करें। आज पारित कानून अतीत की घटनाओं पर लागू नहीं हो सकता। यदि हम आज कुछ करते हैं, तो हम आज और लागू कानून को ध्यान में रखते हुए करते हैं, न कि कल के पिछड़े समायोजन को ध्यान में रखते हुए। कानून की प्रकृति की हमारे विश्वास में स्थापना इस आधार पर की गई है कि प्रत्येक मनुष्य मौजूदा कानून पर भरोसा करके अपने मामलों को व्यवस्थित करने का हकदार है और उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि उसकी योजनाएं पूर्वव्यापी रूप से परेशान हो गई हैं। कानून के इस सिद्धांत को लेक्स प्रोस्पिसिट नॉन रेस्पिसिट के रूप में जाना जाता है: कानून आगे देखता है, पीछे नहीं। जैसा कि फिलिप्स बनाम आयर ((1870) एलआर 6 क्यूबी 1) में देखा गया था, एक पूर्वव्यापी कानून सामान्य सिद्धांत के विपरीत है, वह कानून जिसके द्वारा मानव जाति के आचरण को विनियमित किया जाना है, जब पहली बार भविष्य के कृत्यों से निपटने के लिए पेश किया जाता है, तो उसे तत्कालीन मौजूदा कानून के विश्वास पर किए गए पिछले लेनदेन के चरित्र को नहीं बदलना चाहिए।

पूर्वव्यापीता के विरुद्ध सिद्धांत का स्पष्ट आधार "निष्पक्षता" का सिद्धांत है, जो हर कानूनी नियम का आधार होना चाहिए जैसा कि एल'ऑफिस चेरिफ़िएन डेस फॉस्फेट्स बनाम यामाशिता-शिनिहोन स्टीमशिप कंपनी

लिमिटेड [(1994) 1 एसी 486: (1994) 2 डब्लूएलआर 39: (1994) 1 ऑल ईआर 20 (एचएल) में देखा गया था। इस प्रकार, जो कानून अर्जित अधिकारों को संशोधित करते हैं या जो दायित्व थोपते हैं या नए कर्तव्य लगाते हैं या नई विकलांगता जोड़ते हैं उन्हें संभावित माना जाना चाहिए जब तक कि विधायी न हो इरादा स्पष्ट रूप से अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव देने का है; जब तक कि कानून किसी पूर्व कानून में स्पष्ट चूक की आपूर्ति करने या किसी पूर्व कानून की व्याख्या करने के उद्देश्य से न हो। हमें इस विषय पर उपलब्ध केस कानून की व्यापकता पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उपरोक्त कानूनी स्थिति विभिन्न निर्णयों से स्पष्ट रूप से उभरती है और इस कानूनी स्थिति को पार्टियों के वकील द्वारा स्वीकार किया गया था। किसी भी मामले में, हम थोड़ी देर बाद इस आदेश वाले कुछ निर्णयों का उल्लेख करेंगे।" [पैरा 28 और 29]

25. उपरोक्त निर्णयों की रूपरेखा पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 28, मूल कानून होने के नाते, भावी रूप से संचालित होती है क्योंकि इसकी भाषा से पूर्वव्यापीता स्पष्ट रूप से सामने नहीं आती है। प्रकृति में सुधारात्मक होने के कारण, और कानून के स्पष्टीकरण या घोषणात्मक नहीं होने के कारण, धारा 28(बी) के अंतर्गत आने वाले कुछ समझौतों को पहली बार शून्य बनाकर, यह स्पष्ट है कि अधिकार और देनदारियां जो पहले से ही बीच में हुए समझौतों के परिणामस्वरूप अर्जित हो चुकी हैं। पक्षकारो को छीनने की कोशिश की जा रही है। यह मामला होने पर, हमारा विचार है कि एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच दोनों ने यह मानने में गलती की थी कि संशोधित धारा 28 लागू होगी।

26. यह ध्यान में रखते हुए कि असंशोधित धारा 28 लागू होनी है, उक्त धारा पर ध्यान देना और यह देखना महत्वपूर्ण है कि इसके आवश्यकता तत्व क्या है। सबसे

पहले, किसी भी पक्ष को किसी भी अनुबंध के तहत या उसके संबंध में अपने अधिकारों को लागू करने से पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। दूसरे, इस तरह के पूर्ण प्रतिबंध को सामान्य कानूनी कार्यवाही के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए। राज्यद्वारा स्थापित सामान्य न्यायाधिकरण। तीसरा, इस तरह का पूर्ण प्रतिबंध उस समय की सीमा से भी संबंधित हो सकता है जिसके भीतर पार्टी अपने अधिकारों को लागू कर सकती है।

27. इस बिंदु पर, वर्तमान मामलों के तथ्यों में बैंक गारंटी में सटीक खंड निर्धारित करना आवश्यक है। ऐसा एक खंड इस प्रकार है:

> "...जब तक इस गारंटी के तहत कोई मांग या दावा उपरोक्त तिथि से तीन महीने के भीतर (यानी 30.4.97 को या उससे पहले) हमारे खिलाफ नहीं किया जाता है, उक्त गारंटी के तहत आपके सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हमें राहत मिलेगी और इसके अंतर्गत सभी देनदारियों से मुक्त कर दिया गया।"

28. एक अन्य बैंक गारंटी में निहित एक समान खंड इस प्रकार है: -

> "...बशर्ते, जब तक कि 416.500 मीट्रिक टन 2450 गांठ कच्चे कपास के निर्यात के संबंध में इस गारंटी की समाप्ति की तारीख से 3 महीने के भीतर इस गारंटी के तहत कोई मांग या दावा लिखित रूप में हमसे नहीं किया जाता है, तो उसके बाद हमे इस गारंटी के तहत सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया जायेगा।"

29. उपरोक्त खंडों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी खंड उस समय को सीमित करने का इरादा नहीं रखता है जिसके भीतर अधिकारों को लागू किया जाना है। दूसरे शब्दों में, कोई भी खंड उस सीमा की अवधि को कम करने का इरादा नहीं रखता है जिसके भीतर बैंक गारंटी को लागू करने के लिए मुकदमा लाया जा सकता है।

ऐसा होने पर, इस न्यायालय के निर्णय भारत का खाद्य निगम बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (1994) 3 एससीसी 324 से यह स्पष्ट है कि, वर्तमान मामले के सभी तथ्यों पर लागू होगा।

30. वेंकटचला, न्यायाधिपति और भरूचा, न्यायाधिपति के निर्णय निष्ठा बीमा गारंटी में प्रासंगिक खंड निम्नानुसार निर्धारित किया: -

> "...हालाँकि, अनुबंध की समाप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि की समाप्ति के बाद निगम के पास इस बांड के तहत कोई अधिकार नहीं होगा।"

31. उस मामले में तथ्यों पर, उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनियों की अपील को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया था कि उक्त खंड निगम को संबंधित अनुबंधों की समाप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि की समाप्ति के बाद बीमा कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दायर करने का अधिकार नहीं देता है। उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने माना कि बांड के किसी भी खंड में यह आवश्यक नहीं है कि अनुबंध की समाप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर बांड के तहत अपने अधिकारों को लागू करने के लिए निगम द्वारा मुकदमा दायर किया जाना चाहिए। बांड के खंडों में विज्ञापित प्रतिबंध में निगम के लिए बांड के आधार पर दावा दायर करने की आवश्यकता की परिकल्पना की गई थी, और यदि ऐसा किया गया था, तो बांड के तहत अधिकारों का आह्वान करने के लिए परिसीमा अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा अवधि के भीतर एक मुकदमा दायर किया जा सकता है।

32: एक अलग सहमति वाले फैसले में आर.एम. सहाय, न्यायाधिपति ने अपने फैसले के पैराग्राफ 3 में मामले के कानून पर गौर करने के बाद एक बेहद गहन अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि जहां सीमा के भीतर मुकदमा दायर करना किसी पूर्व शर्त पर निर्भर करता है, तो ऐसी पूर्व शर्त उस सीमा अवधि को कम नहीं करती है

जिसके भीतर मुकदमा दायर किया जा सकता है, वैध होगा और धारा 28 से प्रभावित नहीं होगा। के पैराग्राफ 8 में विद्वान न्यायाधीश ने निर्णय इस प्रकार दिया:-

> "यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सीमा की अवधि को कम नहीं करता है और न ही यह कहीं भी प्रदान करता है कि निगम को छह महीने की समाप्ति के बाद मुकदमा दायर करने से रोका जाएगा। इसे मुकदमा दायर करने के लिए एक शर्त के रूप में माना जा सकता है जो अपीलकर्ता को करना चाहिए। पक्षकारो के बीच सहमत अवधि के भीतर अधिकार का प्रयोग किया है। नोटिस जारी होने पर समझौते के तहत अधिकार लागू किया गया था और कंपनी को राशि का भुगतान करने की आवश्यकता थी। अधिकार का दावा कानून की अदालत में लागू करने की तुलना में एक बात है। समझौता कहीं भी कानून की अदालत में अधिकार के प्रवर्तन से संबंधित नहीं है। यह केवल अधिकार के दावे से संबंधित है। इसलिए, अधिकार का दावा समझौते द्वारा शासित होता है और यह भी जरूरी है कि संबंधित पक्ष को समझौते में दिए गए एक विशेष समय के भीतर अधिकार का दावा करके दूसरे पक्ष को नोटिस देना चाहिए ताकि दूसरे पक्ष को न केवल मांग का पालन करने में सक्षम बनाया जा सके बल्कि मामले में उसे सतर्क भी रखा जा सके। इसे पूरा नहीं करने पर अदालत में कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। चूंकि निगम ने अनुबंध की समाप्ति से छह महीने की समाप्ति से पहले नोटिस जारी किया था, यह फिडेलिटी बीमा खंड के अनुसार था और इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा दायर मुकदमा समय के भीतर था। [पैरा 8]

33. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुजीर गणेश नायक एंड कंपनी, (1997) 4 एससीसी 366 में, इस न्यायालय को यह तय करना था कि क्या बीमा पॉलिसी की शर्त 19 असंशोधित धारा 28 से प्रभावित हुई थी। शर्त 19 इस प्रकार है :-

> "शर्त 19.-किसी भी स्थिति में कंपनी हानि या क्षति होने के 12 महीने की समाप्ति के बाद किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगी जब तक कि दावा लंबित कार्रवाई या मध्यस्थता का विषय न हो।"

34. प्रासंगिक मामले के कानून और खाद्य निगम के फैसले के विस्तृत संदर्भ के बाद, इस न्यायालय ने कहा: -

> "खंड 19 में कहा गया है कि किसी भी मामले में बीमाकर्ता हानि या क्षति होने के बारह महीने की समाप्ति के बाद किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि दावा किसी लंबित कार्रवाई या मध्यस्थता के अधीन न हो। यहां दावा किसी भी कार्रवाई या मध्यस्थता कार्यवाही के अधीन नहीं किया गया था। खंड कहता है कि यदि किसी नुकसान या क्षति के घटित होने के बारह महीने के भीतर दावा दायर नहीं किया जाता है, तो बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी। इसमें कोई विवाद नहीं है कि कोई दावा नहीं किया गया था और न ही बारह महीने की उक्त अवधि के दौरान कोई भी मध्यस्थता कार्यवाही लंबित थी। इसलिए इस खंड का प्रभाव स्वयं अधिकार को समाप्त करने और परिणामस्वरूप दायित्व को भी समाप्त करने का है। वर्तमान मामले के तथ्यों पर ध्यान दें। बीमा कंपनी को 28-4-1977 के पत्र द्वारा पत्र दिनांक 10-5-1977 द्वारा हड़ताल के बारे में सूचित किया गया था। बीमाधारक को सूचित किया गया था कि पॉलिसी के तहत उसकी कोई देनदारी नहीं है। इसे पत्र दिनांक 22-9-1977 द्वारा दोहराया गया था। फिर

भी बारह महीने से अधिक समय बाद 25.10.78 को मांग का नोटिस जारी किया गया और 2.6.80 को मुकदमा दायर किया गया। ऐसी देरी से बचने और इस तरह के विलंबित दावों को हतोत्साहित करने के लिए ही ऐसी बीमा पॉलिसियों में खंड 19 जैसा एक खंड शामिल होता है। यही कारण है कि यदि दावों को तत्परता से प्राथमिकता दी जाती है तो उन्हें आसानी से सत्यापित और निपटान किया जा सकता है, लेकिन अगर यह दूसरा है वैसे, हमें नहीं लगता कि बीमाकर्ता के लिए इसे सत्यापित करना संभव होगा क्योंकि साक्ष्य पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो सकते हैं और यादें धुंधली हो सकती हैं। ज़ब्ती खंड 12 में यह भी प्रावधान है कि यदि दावा किया गया है लेकिन खारिज कर दिया गया है, तो ऐसी अस्वीकृति के तीन महीने के भीतर एक कार्रवाई या मुकदमा शुरू किया जाना चाहिए; ऐसा न करने पर पॉलिसी के तहत सभी लाभ जब्त कर लिए जाएंगे। इसलिए, किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर, अधिकार समाप्त होने के बाद मुकदमा दायर किया गया प्रतीत होता है। यही कारण है कि वल्कन इंश्योरेंस मामले में [(1976) 1 एससीसी 943] समान शर्तों में शामिल एक खंड की व्याख्या करते हुए इस न्यायालय ने कहा: (एससीसी पृष्ठ 952, पैरा 23)

"यह बार-बार माना गया है कि ऐसा खंड अनुबंध अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत नहीं आता है।"

भले ही की गई टिप्पणियाँ ओबिटर डिक्टा की प्रकृति में हों, हमें लगता है कि वे खंड के सही पढ़ने पर आगे बढ़ते हैं।" [पैरा 21]

35. एच.पी. राज्य वन कंपनी लिमिटेड बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (2009) 2 एससीसी 252 में, इस न्यायालय को यह तय करना था कि क्या बीमा पॉलिसी का खंड 6(ii) असंशोधित धारा 28 से प्रभावित है। यह खंड इस प्रकार पठनीय है:-

> "6(ii) किसी भी स्थिति में कंपनी हानि या क्षति होने के 12 महीने की समाप्ति के बाद किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, जब तक कि दावा लंबित कार्रवाई या मध्यस्थता का विषय न हो: यह स्पष्ट रूप से सहमत है और घोषित किया गया है कि यदि कंपनी यहां किसी भी दावे के लिए दायित्व से इनकार करेगी और ऐसा दावा अस्वीकरण की तारीख से 12 कैलेंडर महीनों के भीतर नहीं किया जाएगा, जिसे कानून की अदालत में मुकदमे का विषय बना दिया गया है, तो दावा सभी उद्देश्यों के लिए छोड़ दिया गया माना जाएगा और उसके बाद यहां वसूली योग्य नहीं होगा। .

खाद्य निगम और एस.जी. नायक के मामले के प्रचुर संदर्भ के बाद, इस न्यायालय ने माना कि इस तरह की धाराएं धारा 28 से प्रभावित नहीं होंगी।

36. यह ध्यान में रखते हुए कि उत्तरदाताओं का पहला तर्क हमारे द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, हम दूसरे तर्क के बारीक विवरण में जाना आवश्यक नहीं समझते हैं और यह भी कि क्या 1997 के संशोधन के बाद बैंक गारंटी में उपरोक्त खंड धारा 28 (बी) से प्रभावित होंगे। इसे केवल नोटिस किया जा सकता है; पारित होने में, कि संसद ने 18.1.2013 से 2012 में धारा 28 में किए गए संशोधन द्वारा एक अपवाद (iii) जोड़कर, विशेष रूप से बैंक गारंटी के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी शिकायत का काफी हद तक निवारण किया है। चूंकि हम सीधे तौर पर चिंतित नहीं हैं। इस संशोधन के साथ, यह कहना पर्याप्त है कि यदि किसी पार्टी को दायित्व से मुक्त करने या समाप्त करने के लिए निर्दिष्ट अवधि किसी निर्दिष्ट घटना के घटित होने या न होने की तारीख से एक

वर्ष से कम नहीं है, तो वर्तमान जैसी शर्तें 2013 के बाद लागू होंगी। इसलिए, लागत के संबंध में कोई आदेश दिए बिना अपीलें खारिज की जाती हैं।

अंकित ज्ञान

अपीलें खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।